शुरू करने से होने वाले लाभों को देखते हुए दल इस बात से सहमत हुआ कि इनमें से कुछ कार्यकलापों को "सार्क" संसाधन नेटवर्क द्वारा चलाया जा सकता है। दल ने नोट किया है कि भारत साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग समन्वित करेगा तथा दल ने सिफारिश की है कि भारत-"सार्क" संसाधन केन्द्र के विधान पर उचित निर्णय लेने तक "सार्क" संसाधन नेटवर्क के कार्यकलापों का अस्थायी रूप से समन्वय कर सकता है।

दल ने जोरदार सिफारिश की कि राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र व "सार्क" संसाधन केन्द्र की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

दल ने यह भी स्वीकार किया कि सदस्य देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यक्रमों का विनिमय शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिए :—

1. प्रकाशनों, पोस्टर, मुद्रित सामग्री, शोध पेपर, पत्र-पत्रिकाओं, अध्ययन अध्यापन सामग्री का विनिमय ;

2. शोध खोज, मूल्यांकन रिपोर्टों का विनिमय ;

3. दृश्य-श्रव्य सामग्री का विनिमय ;

4. शिल्पवैज्ञानिक-शिक्षाशास्त्रीय निवेश का विनिमय।

दल ने "सार्क" दृश्य-श्रव्य विनिमय समिति से साक्षरता, उत्तर साक्षरता व सतत शिक्षा विषय पर संयुक्त रूप से टी०वी० कार्य-क्रम निर्मित करने का अनुरोध किया है।

विशेषज्ञ दल की उपर्युक्त सिफारिशें विदेश सचिव संबंधी सार्क स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात कार्यान्वित की जायेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा के महाविद्यालयों को धन का आवंटन

1464. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों को कितना कितना धन आवंटित किया है ;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों ने इन आवंटनों के विरुद्ध रोष प्रकट किया है तथा उपकुलपति के सामने अपनी मांगें रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष के 40.07 करोड़ रु० के आवंटन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली कालेजों को अनुरक्षण अनुदान के लिए 50.00 करोड़ रु० आवंटित किए हैं। कुछ कालेजों ने वित्तीय कठिनाइयों की शिकायत की है। आयोग ने कालेजों को आश्वासन दिया है कि दिल्ली कालेजों को अनुरक्षण अनुदानों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधियां दी जाएंगी।

Revival of public sector DA Committee

1465. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Public Sector DA Committee has been revived after its earlier term expired on March 30;

(b) if so, what were the circumstances that led to allow the Committee to expire and subsequently to revive it;

(c) whether the revived Committee has made any progress; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Tripartite DA Committee set up in September, 1988 under the Chairmanship of Labour Minister had several meetings where various aspects of Dearness Allowance Formula were discussed. As the Committee could not come to any conclusion, Government decided that the existing Industrial Dearness Allowance Formula may continue with a revise rate of Rs. 1.90 per point shift with effect from 1.1.89. As there was considerable representation against the decision of the Government, it was decided to revive the Tripartite Committee whose term had expired on 31st March, 1990.

(c) and (d) The revived Tripartite DA Committee has held three meetings so far. The Committee has not finalised its recommendations till now.

Central Investment in States

1466. SHRI E. BALANANDAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total Central Investment in Kerala as on the 31st December, 1989;

(b) what are the States, where the percentage of Central investment has registered a steady growth; and

(c) what are the States, where the percentage has registered a downward trend over a period of three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) Central Plan investment is made for the country as a whole keeping national priorities in view. These Central programmes/projects in most cases transcend the limits of State boundaries. The fruits of these programmes/projects also get spread all over the country. As such these schemes are not drawn-up State-wise. Hence details of total Central Investment in Kerala as on the 31st December, 1989 are not available. However, estimates of State-wise expenditure of the Central Plan for the Sixth Five Year Plan and the first three years of the Seventh Five Year Plan *viz.*, 1985-86 (Actuals), 1986-87 (RE) and 1987-88 (BE) have been worked out in consultation with the Ministries and are indicated in the enclosed Statement. (*See* Appendix CLV, Annexure No. 47)

दिल्ली में हिन्दी एक वैकल्पिक विषय के रूप में

1467. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार हिन्दी को 12वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता): (क) और (ख) जी, हां। विद्यमान योजना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में हिन्दी वैकल्पिक विषय है, तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू